

25 April The Hindu

Beyond the free trade idealism

- अमेरिका ने भारत के साथ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी है। अमेरिका चाहता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर तथा अमेरिका निर्मित मोटर साइकिलों पर आयात शुल्क कम करें।
- इस बीच विश्व व्यापार संगठन द्वारा विश्व में मुक्त व्यापार व्यवस्था के नियमों पर विचार करना चाहिए कि क्या जिन नियमों द्वारा विश्व में विभिन्न देशों के बीच मुक्त व्यापार किया जा रहा है, इनमें सुधार की आवश्यकता है?
- विश्व के अर्थशास्त्रियों का मानना है की विश्व में मुक्त व्यापार व्यवस्था होनी चाहिए, तथा प्रत्येक देश द्वारा उसी वस्तु का व्यापार किया जाना चाहिए जिसे वह बेहतर रूप से कर सकता है। इससे अन्य सभी देशों को लाभ होगा तथा इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा।
- वैश्विक अर्थव्यवस्था में किसी देश को उस वस्तु का उत्पादन नहीं करना चाहिए, जो दूसरे देशों द्वारा पहले से ही किया जा रहा हो, क्योंकि वे देश तब तक कम कुशलता से उत्पादन करेंगे जब तक वे अच्छी तरह नहीं सीख जाते। इस सिद्धांत के अनुसार भारतीयों को यह सीखने की जरूरत नहीं थी कि ट्रकों बसों और दोपहिया वाहनों का उत्पादन कैसे किया जाए क्योंकि इसका उत्पादन अमेरिकी यूरोपीय और जापानी कंपनियों द्वारा कुशलता से किया जा रहा था जिसे हम कम कीमत पर आयात कर सकते थे।
- मिल्टन फ्रीडमैन जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निर्यात कंपनियों की मदद करते हैं, के अनुसार मुक्त व्यापार का प्रतिरोध उपभोक्ताओं द्वारा नहीं किया जाता बल्कि प्रतिस्पर्धी कंपनियों द्वारा किया जाता है।
- कम विकसित देशों की कंपनियां जो आधारभूत ढांचे की कमी के कारण प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते विकसित देशों की कंपनियों द्वारा ऐसी कंपनियों को आसानी से पीछे कर दिया जाता है।
- मुक्त व्यापार से उपभोक्ताओं को कम कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है इसलिए यह लाभदायक है।
- आयात करने के लिए किसी देश के नागरिकों को उपलब्ध उत्पादों और सेवाओं को खरीदने के लिए आय को आवश्यकता है, और इसलिए रोजगार की आवश्यकता होती है।
- किसी देश की सरकार द्वारा अपने देश के नागरिकों के लिए रोजगार के लिए प्रयास किए जाने चाहिए इसके लिए घरेलू उत्पादक को प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए ताकि रोजगार के अवसर पैदा हो सके, इसके लिए प्रभावी औद्योगिक नीति की आवश्यकता है और उन क्षमताओं को विकसित करके यह उन देशों के उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है जो पहले विकसित हुए थे।
- 1990 में मुक्त व्यापार हेतु भारत ने आयात की शर्तों को उदार बनाया और भारतीय उपभोक्ताओं को दुनिया से उपलब्ध विभिन्न प्रकार के उत्पादों का लाभ हुआ। 1990 में चीन भारत की तुलना में 10 गुना बड़ी विनिर्माण क्षमता वाला राष्ट्र था इसका पूंजीगत उत्पादन क्षेत्र 50 गुना बढ़ा था जो न केवल भारतीय बाजार चीनी उत्पादों से भरा था बल्कि विश्व के अन्य देशों को भी दूरसंचार व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बेच रहा था।
- भारत की जीडीपी वृद्धि भारत की बड़ी युवा आबादी के लिए पर्याप्त रोजगार पैदा नहीं कर पा रहे हैं जबकि भारत की अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन प्रमुख घटक होना चाहिए।
- भारत द्वारा घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु 'औद्योगिक नीति' की आवश्यकता की सिफारिश की किन्तु विश्व बैंक और यू.एस. ने इसे एक पुराना विचार बताते हुए औद्योगिक नीति के स्थान पर सुधार के उपाय पर जोर दिया। इनके अनुसार अगर भारत में उद्योग नहीं बढ़ रहे हैं तो इसकी कारण पर्याप्त सुधारों का न होना बताया साथ ही भारत को व्यापार बाधाओं को कम करने के तर्क दिए।
- रोजगार का सृजन अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण विषय है, इस पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए
- सभी पार्टियों द्वारा चुनाव पूर्व रोजगार व आय वृद्धि के लिए ऐसी घोषणाएं की जाती हैं जो आर्थिक रूप से संधारणीय नहीं होगी।

- भारत के नीति निर्माताओं को आर्थिक विकास हेतु आय बढ़ावे के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करना चाहिए।
- भारत द्वारा वैश्विक व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए औद्योगिक नीति तथा रोजगार सृजन हेतु निवेश किया जाना चाहिए। उन सभी क्षेत्रों में निवेश किया जाना चाहिए जो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पर्यटन और आतिथ्य उद्योग। भारत की सांस्कृतिक और प्राकृतिक सुंदरता व विविधता का लाभ उठाते हुए सभी हिस्सों में लाखों छोटे उद्यम विकसित किए जाने चाहिए।
- प्रशिक्षित युवाओं द्वारा छोटे उद्यमों का विकास डिजिटल तकनीकों प्रयोग, विनिर्माण व सेवा क्षेत्र में निर्यात के अवसर प्रदान कर सकती है।
- पूर्व-उदारीकरण युग में सरकार ने उत्पादन और प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र को स्वदेशी तकनीक द्वारा विकसित किया गया। ऑटोमोबाइल क्षेत्र भारतीय उपभोक्ताओं हेतु रोजगार व आय सृजक क्षेत्र बने, अब वैश्विक बाजार में निर्यातक भी है। इसके विपरीत इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में गिरावट आई है, जबकि चीन का विकास हुआ है।
- भारत ने 1996 में विश्व व्यापार संगठन के सूचना प्रौद्योगिकी समझौते पर हस्ताक्षर किए और आइटी से संबंधित निर्मित उत्पादों पर आयात शुल्क घटाकर शून्य कर दिया जबकि चीन कुछ समय के लिए इस समझौते से पीछे हट गया और अपने घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती दी।
- विश्व व्यापार संगठन द्वारा मुक्त व्यापार के आदर्शवाद की आड़ में विकसित देशों को कंपनियों के निर्यात की बाधाओं को कम करने की जगह सभी देशों के नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु नियम बनाए जाने चाहिए।
- भारत को मजबूत औद्योगिक नीति तथा आय व रोजगार की नीति से व्यापार नीति का मार्गदर्शन करना चाहिए।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न- “वर्तमान में वैश्विक परिदृश्य असंतुलित व्यापार के कारण व्यापारिक संबंधों में संतुलन बना पाने में असफल हो रहा है।” वैश्विक व्यापार को दिशा-निर्देशित करने में विश्व व्यापार संगठन किस हद तक अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने सफल हो पा रहा है। चर्चा कीजिए।

Taking advantage of BRI

- चीन की महत्वकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव द्वारा चीन दावा कर रहा है कि दुनिया के विभिन्न देश एक-दूसरे के नजदीक आ जाएंगे व आर्थिक सहयोग के साथ ही आपसी संपर्क बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। छह साल पहले चीन ने इस परियोजना को दुनिया के सामने रखा। हालांकि बहुत ऐसे देश भी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। इनमें भारत के साथ अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका का कहना है कि चीन छोटे-छोटे देशों को कर्ज के भंवर में फंसाना चाहता है जबकि भारत के लिए ये मुद्दा संप्रभुता से जुड़ा है।
- चीन ने अपने ऐतिहासिक व्यापारिक वर्चस्व को पुनः हासिल करने के लिए इस परियोजना को शुरू किया है। वर्तमान में यह BRI का दूसरा वैश्विक सम्मेलन है जिसमें 37 देशों के साथ विश्व के अलग-अलग राष्ट्रों के 1,000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।
- भारत का BRI से संदर्भ अपनी संप्रभुता को लेकर है जिसमें चीन-पाक आर्थिक गलियारे को लेकर भारत ने अपना विरोध दर्ज कराया है और BRI के सम्मेलन का बहिष्कार किया है।
- भारत में कुछ आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होना चाहिए परन्तु सामरिक तौर पर कुछ विशेषज्ञ इस मत का विरोध करते हैं।
- चीन की यह परियोजना वैश्विक पहुंच हेतु एशिया के नेतृत्व में नए आयाम के आगमन का संकेत देती है। जब 21वीं सदी में एशिया विश्व के केंद्र में है, इसमें ऐसे में आधारभूत संरचना की विकास परियोजनाएं एशिया के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी।
- चीन की जनसंख्या एशिया की कुल आबादी की एक तिहाई है लेकिन 2050 तक इसकी कार्यशील आयु जनसंख्या में कमी आएगी ऐसे में भारत को जनसंख्या लाभांश का लाभ मिल पायेगा।
- बीआरआई का वैश्विक प्रसार G7 आर्थिक एजेंडा के अंत का संकेत देता है, हाल ही में G7 का सदस्य देश इटली BRI में शामिल हुआ है। अमेरिका की सार्वजनिक आपत्ति के बावजूद ब्रिटेन एशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में शामिल हुआ। एशियाई व्यवस्था उनकी जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करता है, क्योंकि पुरानी व्यवस्था ढह रही है।
- एशियाई विकास बैंक, एशिया में आर्थिक विकास का प्रमुख चालक सिद्ध हो रहा है। BRI की सबसे बड़ी विशेषता परिवहन, ऊर्जा संचरण और संचार की भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे का नेटवर्क है, जो उन्नत विनिर्माण और नवाचार आधारित कंपनियों के लिए बाजारों के साथ सामंजस्य स्थापित करता है।
- कुछ देशों द्वारा BRI की आलोचना पारदर्शिता को लेकर की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के साथ संबंधों के माध्यम से बहुपक्षवाद के मानकों की ओर बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष BRI को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान के रूप में वर्णित करता है और BRI द्वारा भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय विधियों का पालन किया जायेगा।
- BRI के रणनीतिक उद्देश्य भी रहें हैं जिसे लेकर अन्य देशों द्वारा इसकी आलोचना की जा रही है। यदि चीन अपनी उपनिवेशी व रणनीतिक उद्देश्यों को कम करता है तो भारत द्वारा इसमें शामिल होने के लिए विचार किया जा सकता है।
- भारत की संप्रभुता को प्रभावित करने वाली पाक-चीन-आर्थिक गलियारा परियोजना पर अपना पक्ष रखते हुए इसे बंद करने हेतु प्रस्ताव रखना चाहिए तथा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ कनेक्टिविटी के लिए योजनाओं के साथ जोड़कर जाना चाहिए साथ ही इस परियोजना को बहुपक्षीय संधि की दिशा देने का प्रयास करना चाहिए।

Just recompense (क्षतिपूर्ति)

- बिलकिस बानो के लिए क्षतिपूर्ति भयावह अपराध के लिए राज्य के दायित्व को रेखांकित करती है।
- सुप्रीम कोर्ट ने 23 अप्रैल 2019 को गुजरात सरकार ने बिलकिस बानों के लिए मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपये का, सरकारी नौकरी और आवास देने का निर्देश दिया है। बिलकिस बानो साल 2002 में हुए गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई थी।
- गुजरात सरकार ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोमाई की अध्यक्षता वाली पीठ को सूचित किया कि इस मामले में चूक करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उनके पेंशन लाभ रोक दिए गए हैं और बॉम्बे उच्च न्यायालय ने जिस आइपीएस अधिकारी को दोषी माना है, उसे दो रैंक डिमोट किया गया है।
- गुजरात सरकार ने बिलकिस बानों को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपये देने का प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका में राज्य सरकार से अनुकरणीय मुआवजे की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मुआवजा राशि को 10 गुना बढ़ा दिया।
- सीबीआई ने चार्जशीट में 18 लोगों को दोषी पाया था। इसमें 5 पुलिसकर्मी समेत दो डॉक्टर भी शामिल थे जिन्होंने आरोपी की मदद करने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ की थी।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला:-

- सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के मामले में गलत जांच करने में दोषी पाए गए पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही के बाद उन पर तुरंत सजा लागू करने का आदेश दिया है।
- इस निर्णय में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357A में संशोधन किया गया। जिसके तहत हर राज्य सरकार को एक निधि तैयार करने की योजना तैयार करनी होती है जहां से पीड़ितों और उनके आश्रितों को क्षतिपूर्ति की जा सके। केंद्र के पास भी पीड़ित क्षतिपूर्ति कोष होता है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण ने यह कोष तैयार किया था। आवश्यकता है कि सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाये।